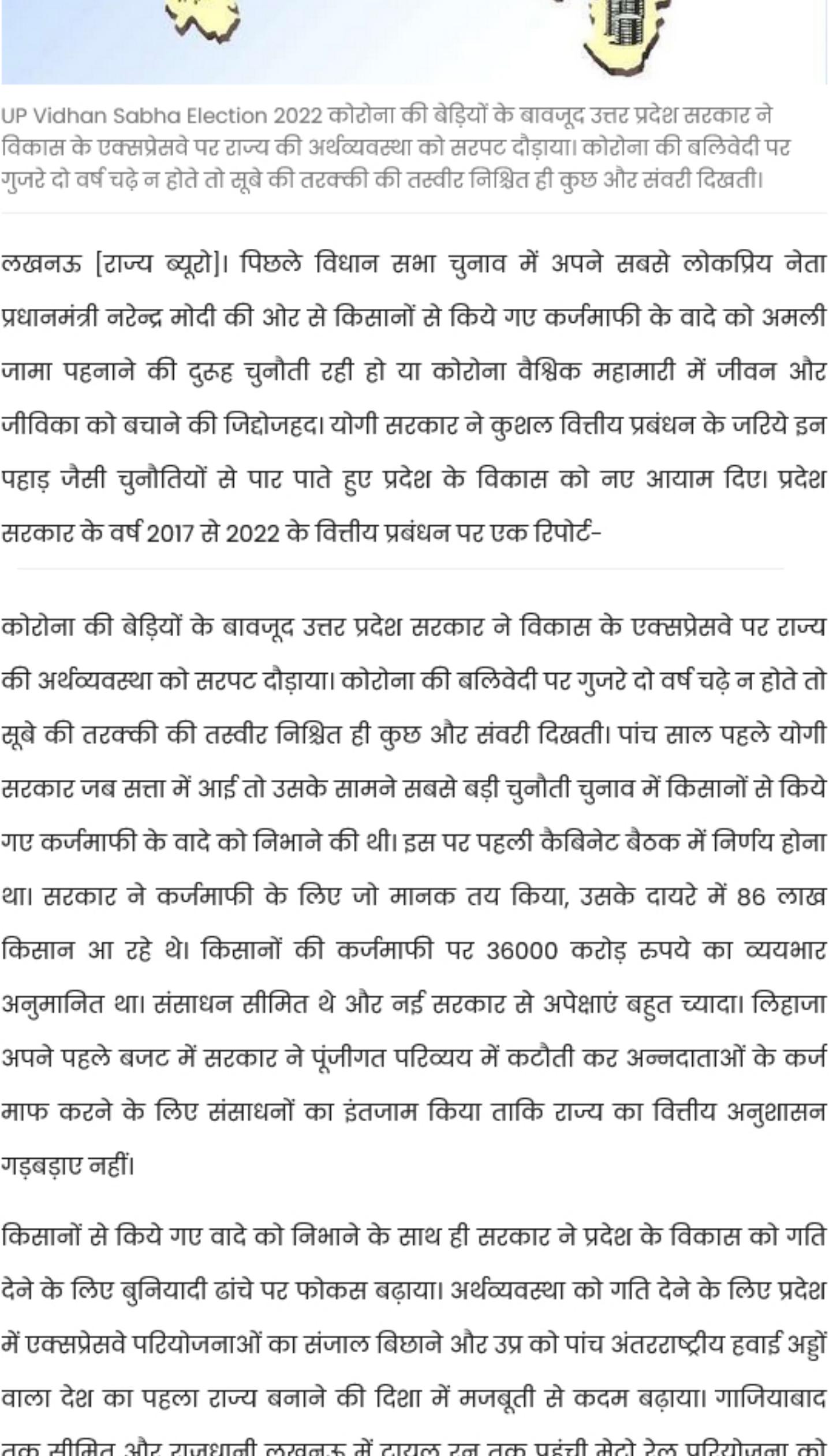


UP Election 2022: न आता कोटोना तो विकास भरता और फर्टी, चुनौतियों से बखूबी निपटी योगी सरकार

Author: Umesh Tiwari

Publish Date: Thu, 24 Feb 2022 07:00 AM (IST) | Updated Date: Thu, 24 Feb 2022 10:45 AM (IST)



UP Vidhan Sabha Election 2022 कोटोना की बेड़ियों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के एक्सप्रेसवे पर राज्य की अर्थव्यवस्था को सरपट दौड़ाया। कोटोना की बलिवेदी पर गुजरे दो वर्ष चढ़े न होते तो सूबे की तरक्की की तरवीर निश्चित ही कुछ और संवरी दिखती।

लखनऊ [राज्य ब्लूटो]। पिछले विधान सभा चुनाव में अपने सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से किसानों से किये गए कर्जमाफी के बादे को अमली जामा पहनाने की दुनह चुनौती रही हो या कोटोना वैशिक महामारी में जीवन और जीविका को बचाने की जिद्दोनहदा योगी सरकार ने कुथल वित्तीय प्रबंधन के जरिये इन पहाड़ जैसी चुनौतियों से पार पाते हुए प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए। प्रदेश सरकार के वर्ष 2017 से 2022 के वित्तीय प्रबंधन पर एक रिपोर्ट-

कोटोना की बेड़ियों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के एक्सप्रेसवे पर राज्य की अर्थव्यवस्था को सरपट दौड़ाया। कोटोना की बलिवेदी पर गुजरे दो वर्ष चढ़े न होते तो सूबे की तरक्की की तरवीर निश्चित ही कुछ और संवरी दिखती। पांच साल पहले योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में किसानों से किये गए कर्जमाफी के बादे को निभाने की थी। इस पर पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय होना था। सरकार ने कर्जमाफी के लिए जो मानक तय किया, उसके दायरे में 86 लाख किसान आ रहे थे। किसानों की कर्जमाफी पर 36000 करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित था। संसाधन सीमित थे और नई सरकार से अपेक्षाएं बहुत च्यादा। लिहाजा अपने पहले बजट में सरकार ने पूंजीगत परिव्यय में कटौती कर अन्नदाताओं के कर्ज माफ करने के लिए संसाधनों का इंतजाम किया ताकि राज्य का वित्तीय अनुशासन गड़बड़ाए नहीं।

किसानों से किये गए बादे को निभाने के साथ ही सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर फोकस बढ़ाया। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का संजाल बिछाने और उप्र को पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाया। गाजियाबाद तक सीमित और राजधानी लखनऊ में द्रायल रन तक पहुंची मेट्रो ट्रेल परियोजना को सूबे के पांच और शहरों में पहुंचाया। सभी को रवाउथ्य सुविधाएं सुलभ कराने की सरकार की यह छँड़ इच्छाथकि ही थी कि बीते पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में 35 नए सरकारी मैटिकल कालेज खुले जबकि 16 सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर स्थापित किये जा रहे हैं।

इसी अवधि में गोरखपुर और रायबरेली में एम्स ने आकार लिया। राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। सहाटनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ाए। अधूरी रिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लायों हेक्यूर जमीन झींचने का इंतजाम किया। सड़क-सेतु, बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार दी।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लक्ष्य को स्वीकार कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'सबका साथ, सबका विकास' के नामे को साकार करने के लिए बजट का आकार बढ़ाने की हिमायत की। बजट को ईंधन देने के लिए उन्होंने राज्य के कर राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया। यही बजह थी कि वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 3,84,659.71 करोड़ रुपये था जो 2021-22 में बढ़कर 5,50,278.78 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान उप्र का सकल राज्य घटेलू उत्पाद बढ़ा और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी।

कोटोना महामारी ने सरकार के सामने भी घोट आर्थिक संकट खड़ा किया। कोविड के कारण सरकारी खजाने को तगड़ी चोट लगी। नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2020-21 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में लक्ष्य के सापेक्ष 27.78 प्रतिशत की कमी आई। वैशिक महामारी का असर राज्य के सकल घटेलू उत्पाद पर पड़ा और प्रति व्यक्ति आय पर भी। हालांकि दोनों मोर्चों पर उप्र की गिरावट राष्ट्रीय औसत से कम ही रही। कोटोना महामारी से उपनी विषम परिस्थितियों में जीवन और जीविका बचाने में जुटी राज्य सरकार को न चाहते हुए भी विकास परियोजनाएं के लिए मुद्री थोड़ी भींचनी पड़ी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पूरा रुपाल रखा और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मानकों पर खटी उतारी।

राजस्व खर्च को नियंत्रित कर पूंजीगत व्यय बढ़ाया : लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो.मनोज कुमार अग्रवाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बजट का आकार बढ़ाया। विकास के लिए खर्च बढ़ाए। बढ़े खर्च के लिए संसाधन जुटाए। उप्र को जीएसटी का फायदा मिला। वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया, उप्र को संसाधन जुटाने में इसका भी लाभ मिला। सबसे अहम पहलू यह है कि योगी सरकार ने राजस्व खर्च को नियंत्रित करके पूंजीगत व्यय को तेजी से बढ़ाया है। सुधासन के कारण गिरी निवेश बढ़ा है। कोटोना संक्रमण न होता तो निवेश के और अच्छे परिणाम मिलते। जनधन योजना, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का परिणाम यह हुआ कि कोटोना महामारी के झटके से उपर तेजी से उबर सका।

कितना मिला कर राजस्व (करोड़ रुपये)

■ वर्ष - लक्ष्य - प्राप्ति

■ 2017-18 - 111501.9 - 97393

■ 2018-19 - 122700 - 120121.85

■ 2019-20 - 140176 - 122825.83

■ 2020-21 - 186345 - 119897.3

■ 2021-22 - 186345 - 160349.78

■ (स्रोत : वित्त विभाग, उप्र)

ऐसे बढ़ा बजट का आकार

■ वर्ष - आकार (करोड़ रुपये)

■ 2017-18 - 3,84,659.71

■ 2018-19 - 4,28,384.52

■ 2019-20 - 4,79,701.1

■ 2020-21 - 5,12,860.72

■ 2021-22 - 5,50,278.78

■ (स्रोत : वित्त विभाग, उप्र)

पूंजीगत परिव्यय

■ वर्ष - धनराशि (करोड़ रुपये)

■ 2017-18 - 39,087.97

■ 2018-19 - 62,463.41

■ 2019-20 - 59,998.03

■ 2020-21 - 68,253.87

■ 2021-22 - 1,13,767.7

■ (स्रोत : वित्त विभाग, उप्र)

यूपी का सकल घटेलू उत्पाद (करोड़ रुपये)

■ वर्ष - जीएसटीपी

■ 2016-17 - 12,88700

■ 2017-18 - 14,39,706

■ 2018-19 - 15,82,853

■ 2019-20 - 17,10,496

■ 2020-21 - 17,17,505

■ (स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग)

यूपी में प्रति व्यक्ति आय

■ वर्ष - प्रति व्यक्ति आय

■ 2016-17 - 52,671 रुपये

■ 2017-18 - 57,994 रुपये

■ 2018-19 - 62,380 रुपये

■ 2019-20 - 66,136 रुपये

■ 2020-21 - 65,338 रुपये

■ (स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग)